जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 267 प्रभात चूरू, शुक्रवार 23 जनवरी, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

ग्रोथ को लेकर आशावादी है उद्योग जगत

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जनवरी। केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले भारत के उद्योग जगत (इंडिया इंक) का रुख देश की आर्थिक दिशा को लेकर सकारात्मक बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चित माहौल के बावजूद, उद्योग जगत के अधिकांश नेताओं ने निरंतर विकास को लेकर भरोसा जताया है। यह भावना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के प्री-बजट सर्वेक्षण 2026-27 से उभरकर सामने आई है, जिसमें आगामी बजट से पहले, उद्योग की अपेक्षाओं और

- औद्योगिक संगठन फिक्की के प्री बजट सर्वे में 80 प्रतिशत उद्योगपतियों ने भारत की विकास संभावनाओं पर भरोसा जताया।

नीतिगत प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है।

सर्वेक्षण व्यापक स्तर पर आशावाद को दर्शाता है। लगभग 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भारत की विकास संभावनाओं पर भरोसा जताया है। करीब आधे उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026-27 में सकल घरेलू उत्पाद (ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन-जीडीपी) की वृद्धि दर 7-8 प्रतिशत के दायरे में बनी रहेगी, जो अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की

(शेष पृष्ठ 5 पर)

ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकियां नाकामयाब रही ग्रीनलैंड प्रकरण में

ट्रंप अपने तमाम नाटकीय उद्घोषों के बावजूद यूरोपीय देशों की एकता को नहीं तोड़ पाए और अन्ततोगत्वा टैरिफ बढ़ाने की धमकी वापस ली

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जनवरी। कई हफ्तों की तीखी बयानबाजी के बाद, यूरोप के कई देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी से राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प हट गए, यह उनके दूसरे कार्यकाल की विदेश नीति में एक अहम मोड़ को दर्शाता है। इसका कारण व्यापारिक अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि भू-राजनीति थी: ग्रीनलैंड और आर्कटिक सुरक्षा पर एक जल्दबाज़ी में तैयार किया गया भविष्य के समझौते का ढांचा, जिसे नाटो के महासचिव मार्क रुटे की मध्यस्थता से तैयार किया गया। यह प्रकरण ट्रम्प की दबाव-आधारित कूटनीति की हदों, यूरोप की सामूहिक शक्ति की मजबूती और उनके अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अंतर्विरोधों को उजागर करता है।

ट्रम्प चाहते हैं कि उनका रुख परिवर्तन रणनीतिक कदम लगें, और यहाँ तक कि वे विजयी लगे। टैरिफ निलंबित कर वे लचीलापन दिखाते हैं, पर ग्रीनलैंड का हवाला देकर वे खुद की सुरक्षा को लेकर जुनूनी, कठोर यथार्थवादी के रूप में पेश करते हैं। लेकिन घटनाक्रम और समयक्रम कुछ

- ट्रंप अपने प्रथम कार्यकाल से ही यह सनक भरी शिकायत करते रहे हैं कि अमेरिका को नाटो से मिलता ही क्या है, केवल यूरोप की सुरक्षा प्रदान करने का बोझ।
- पर, अब ट्रंप को ग्रीनलैंड के मसले पर, नाटो की ''शरण'' में जाना पड़ा और नाटो के सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से एक ''फेमवर्क'' निकालना पड़ा।
- ट्रंप डावोस सम्मेलन में एक घंटे के भाषण से विश्व में अमेरिका के प्रभुत्व को जताना चाहते थे, पर, उनके भाषण में केवल रीति-नीति के विरोधाभासी तर्क ही उजागर हुए।
- और अंत में उन्हें मंच से कहना पड़ा, अमेरिका का मकसद सारे प्रकरण में विश्व की सुरक्षा थी, न कि ग्रीनलैंड की खनिज सम्पदा को हड़पना।
- इस ग्रीनलैंड प्रकरण ने यह भी उजागर किया, अन्य देशों की एकता व संयम ट्रंप की धमकियों का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

'एआई जॉब मार्केट को तेजी से बदल रहा है'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जनवरी। वाइट कॉलर कर्मचारियों (मैनेजमैंट या बौद्धिक कार्य करने वाले) के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। बिल गेट्स का कहना है कि सरकारें इसके लिए तैयार नहीं हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक ने दावोस में आयोजित अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में चेतावनी दी कि आर्टीफिशियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अपेक्षा से कहीं तेज़ी से नौकरी-बाज़ार को नया आकार देने जा

- बिल गेट्स ने दावोस में चेतावनी देते हुए कहा कि यह जरूरत से ज्यादा तेजी से हो रहा है और इसका असर बौद्धिक कार्य वाली नौकरियों पर पड़ेगा।

रही है, और तैयारी के लिए समय बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है।

बीमारी के इलाज से लेकर शिक्षा तक में एआई की संभावनाओं को स्वीकार करते हुए, गेट्स ने चेताया कि यदि इसे सही ढंग से प्रबंधित (मैनेज्ड) नहीं किया गया, तो कार्यबल, भर्ती के पैटर्न और आर्थिक न्याय पर इसका प्रभाव गंभीर हो सकता है।

उनके अनुसार, इन चुनौतियों की

(शेष पृष्ठ 5 पर)

मध्य प्रदेश का शहर, धार पुलिस छावनी बना

8,000 पुलिसकर्मी, जिनमें सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स आदि तैनात किये गए

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार शहर में स्थित विवादित भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर में इस शुक्रवार हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी है।

हिंदु समुदाय को शुक्रवार को पड़ रहे हिंदू पर्व बसंत पंचमी के अवसर पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति दी गई है, जबकि मुस्लिम समुदाय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक अपनी शुक्रवार की नमाज़ अदा कर सकेगा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि नमाज़ के लिए आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक सूची जिला प्रशासन को दी जानी चाहिए।

पीठ ने दोनों पक्षों से आपसी सम्मान का ध्यान रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य व जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील भी की।

अदालत एक हिंदू संगठन "हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस" (एच एफ जे) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बसंत पंचमी के दिन हिंदुओं को पूजा का विशेष अधिकार देने की मांग की गई थी।

यह आवेदन 2 जनवरी को एच एफ जे की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर किया गया था और इसे तत्काल सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। याचिका में कहा गया था कि "भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण" का 2003 का आदेश उन परिस्थितियों को संबोधित नहीं करता, जब बसंत पंचमी शुक्रवार की नमाज़ के साथ पड़ती है।

- मसला था, भोजशाला, ग्यारहवीं शताब्दी के वाग् देवी (सरस्वती देवी) के मंदिर में हिंदुओं को पूजा-अर्चना करने का न्यायालय द्वारा प्रदत्त अधिकार।
- इस स्थल को मुसलमान कमाल मौला की मस्जिद मानते हैं।
- न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार, हिंदू बसंत पंचमी को प्रातःकाल से सूर्यास्त तक अपनी पूजा-अर्चना कर सकते हैं तथा मुसलमान शुक्रवार के दोपहर एक बजे से तीन बजे तक नमाज़ अदा कर सकते है।
- पर, न्यायालय की व्यवस्था में, इस बात का कोई प्रावधान नहीं किया गया कि जब बसंत पंचमी, शुक्रवार को पड़े, जैसा 23 जनवरी को है, तब क्या किया जाए।
- प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है, उन लोगों की लिस्ट मांगी गई है, जो शुक्रवार को वहाँ नमाज़ अदा करने जाना चाहते हैं। पुलिस पैदल और वाहनों में लगातार पैट्रोलिंग कर रही है और सीसीटीवी के मार्फत चौकसी बरत रही है तथा सोशल मीडिया के गतिविधि पर भी निगाह रखे हुए है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)